भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *263

जिसका उत्तर 18 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

कोयला क्षेत्र का आधुनिकीकरण

***263. श्री नीरज डांगी:**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कोयला क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के लिए खनन कार्यों में नई प्रौद्योगिकियों को अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग से कोयला खनन की लागत और दक्षता प्रभावित हुई है;

(घ) क्या आधुनिक प्रौद्योगिकियों के कारण श्रमिकों की आवश्यकता में कमी आई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कोयला क्षेत्रों के आधुनिकीकरण और विकास के लिए निवेश की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ड.) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

"कोयला क्षेत्र का आधुनिकीकरण" के संबंध में श्री नीरज डांगी, माननीय संसद सदस्य द्वारा दिनांक 18.08.2025 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *263 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): कोयला मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने प्रचालन की दक्षता बढ़ाने के लिए (अन्वेषण, आयोजना, प्रचालन से लेकर ऑफ-टेक तक) अपनी वैल्यू चेन में निम्नलिखित प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं को अपनाया है। इनमें ओपनकास्ट खानों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ सरफेस माइनर्स, उच्च क्षमता वाले एक्सकेवेटर, डंपर्स की तैनाती; हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी का मानकीकरण; भूमिगत खानों में सतही खनिकों, लॉन्गवॉल और हाईवॉल की तैनाती; आधुनिक स्ट्रेटा निगरानी उपकरण की तैनाती; मैन राइडिंग सिस्टम को अपनाना; भूकंपीय सर्वेक्षण, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का उपयोग; कर्मचारी संसाधन आयोजना (ईआरपी) प्रणाली का कार्यान्वयन; आईटी-आधारित पहलों का कार्यान्वयन; 'डिजिकोल' नामक डिजिटल परिवर्तन प्रायोगिक परियोजना का कार्यान्वयन और एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी); 5जी कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क की शुरुआत; ड्रोन का उपयोग; और कोयला हैंडलिंग का मशीनीकरण करना शामिल हैं।

(ग) और (घ): सीआईएल (कोल इंडिया लिमिटेड) में, प्रति टन कोयले की उत्पादन लागत (सीपीटी) वित्त वर्ष 2021-22 में 1406.00 रुपए से घटकर वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 1391.00 रुपए हो गई है और प्रति मैन शिफ्ट कुल आउटपुट (ओएमएस) भी वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 9.53 टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 12.30 टन हो गया है।

एससीसीएल में, प्रति टन उत्पादन लागत वर्ष 2022-23 के 3404 रुपए से घटकर 2024-25 में 2877 रुपए हो गई है। एससीसीएल में प्रति मैनशिफ्ट कुल उत्पादन वर्ष 2022-23 के 5.31 टन से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 5.79 टन हो गया है।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड के तालाबीरा II और III ओसीपी में, प्रति टन कोयला उत्पादन लागत (सीपीटी) वित्त वर्ष 2022-23 में 10.03 मि.ट. कुल कोयला उत्पादन के साथ 917.20 रु. से घटकर वित्त वर्ष 2023-24 में 12.64 मि.ट. के कुल कोयला उत्पादन के साथ 890.60 रु. हो गई। तथापि, वित्त वर्ष 2024-25 में कोयला उत्पादन उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 17.20 मि.ट. होने के कारण प्रति टन कोयला उत्पादन की लागत (सीपीटी) 986.53 रु. हो गई है। प्रति मैन शिफ्ट कुल उत्पादन (ओएमएस) भी वित्त वर्ष 2023-24 के 54.89 टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 66.40 टन हो गया।

मशीनीकरण और आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने से, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भूमिगत खानों में कोयले की मैन्युअल कटाई बंद कर दी गई है। इस बदलाव से श्रमिकों की सुरक्षा और समग्र कामकाजी माहौल में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

(ङ.): वित्त वर्ष 2024-25 में, सीआईएल ने आधुनिकीकरण, अवसंरचना, भूमि और कोलफील्ड्स के विकास के लिए कुल 21775.99 करोड़ रु. का पूंजी निवेश किया है और एससीसीएल ने खानों और कोयला निकासी अवसंरचना के विकास के लिए 1524.62 करोड़ रु. का पूंजी निवेश किया है। एनएलसीआईएल की तालाबीरा II और III ओसीपी (ओपन कास्ट परियोजना) एमडीओ (माइन डेवलपर और ऑपरेटर) मोड में प्रचालित की जा रही है और इसमें ₹38.00 करोड़ के अनुमानित निवेश से 6 सतही खनिक तैनात किए गए हैं।

****